



## काउंटरगि अमेरिकाज़ एडवर्सरज़ थ्रू सैंकशंस एक्ट (CAATSA)

### प्रलिस के लयि:

CAATSA, S-400 मसिइल प्रणाली ।

### मेन्स के लयि:

भारत के लयि CAATSA छूट के नहितिारथ, अमेरिका-भारत संबंध, रूस-भारत संबंध ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवि नेनेशनल डफिंस ऑथराइज़ेशन एक्ट (NDAA) में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें **काउंटरगि अमेरिकाज़ एडवर्सरज़ थ्रू सैंकशंस एक्ट (CAATSA)** के तहत भारत को प्रतबिंधों के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है ।

- यह भारत को स्वतंत्र रूप से अमेरिकी प्रतबिंधों के भय के बिना रूस की **S-400 मसिइल प्रणाली** को खरीदने की अनुमति देगा ।
- नेशनल डफिंस ऑथराइज़ेशन (NDAA) कानून है जिससे कॉन्ग्रेस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राज्य की रक्षा एजेंसियों की नीतियों और संगठन में बदलाव करने के लयि पारति करती है तथा इस पर मार्गदर्शन प्रदान करती है कि सैन्य क्षेत्र को आवंटति राशिको कैसे खर्च किया जा सकता है ।

## प्रस्तावति संशोधन:

- संशोधन अमेरिकी प्रशासन से आग्रह करता है कि वह चीन जैसे हमलावरों को रोकने में मदद करने हेतु भारत को काउंटरगि अमेरिकाज़ एडवर्सरज़ थ्रू सैंकशंस एक्ट (CAATSA) के तहत छूट प्रदान करने के लयि अपने अधिकार का उपयोग करे ।
- कानून में कहा गया है कि महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत पहल (ICET) कृत्रमि बुद्धमिता, क्वांटम कंप्यूटगि, जैव प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस तथा अर्द्धचालक वनिर्माण में नवीनतम प्रगति को संबोधति करने के लयि दोनों देशों में सरकारों, शकिषावर्दिों एवं उद्योगों के बीच घनषिठ साझेदारी वकिसति करने हेतु एक स्वागत योग्य और आवश्यक कदम है ।

## CAATSA

### परचिय:

#### ○ अमेरिकी कानून:

- CAATSA एक अमेरिकी कानून है जिससे वर्ष 2017 में लागू किया गया था तथा इसका मुख्य उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है ।
- अका शीर्षक II मुख्य रूप से **यूकरेन में इसके सैन्य हस्तकषेप** और वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में इसके कथति हस्तकषेप की पृष्ठभूमि में इसके तेल और गैस उद्योग, रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र, वतितीय संस्थानों जैसे रूसी हतिों पर प्रतबिंधों से संबधति है ।
- अधनियिम की धारा 231 **अमेरिकी राष्ट्रपति** को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ **"महत्त्वपूर्ण लेन-देन"** में लगे व्यक्तियों पर अधनियिम की धारा 235 में उल्लिखति 12 सूचीबद्ध प्रतबिंधों में से कम-से-कम पाँच प्रतबिंधों को आरोपति करने का अधिकार देती है ।
  - अधनियिम की धारा 231 के भाग के रूप में अमेरिकी वदिश वभिग ने 39 रूसी संस्थाओं को अधसिचति किया है, जिनके साथ संबध रखने पर तीसरे पक्ष को प्रतबिंधों के लयि उत्तरदायी बनाया जा सकता है ।

- **प्रतबिंध जो भारत को प्रभावति कर सकते हैं** : केवल दो प्रतबिंध ऐसे हैं जो भारत-रूस संबधों या भारत-अमेरिका संबधों को प्रभावति कर सकते हैं ।

- **बैंकगि लेन-देन का नषिध**: इनमें से पहला, जिसका भारत-रूस संबधों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, **"बैंकगि लेन-देन का नषिध"** है ।

- इसका परिणाम यह होगा कि भारत के लयि एस-400 ससि्टम की खरीद हेतु रूस को अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने में

कठनाई होगी। यह भारत की स्पेयर पार्ट्स, घटकों, कच्चे माल और अन्य सेवाओं की खरीद को भी प्रभावित करेगा।

○ वर्ष 2020 में **तुर्की को S-400 प्रणाली की खरीद** के लिये मंजूरी प्रदान की गई थी।

● **नरियात मंजूरी:**

○ "नरियात मंजूरी" प्रतर्बिंध के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें **भारत-अमेरिका सामरिक और रक्षा साझेदारी** के पूरी तरह से पटरी से उतरने की आशंका है, क्योंकि यह अमेरिका द्वारा नरियात कसिी भी वस्तु के लाइसेंस एवं नरियात को अस्वीकार कर देगा।

○ **छूट मानदंड:**

● अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ष 2018 में 'केस-बाइ-केस' आधार पर CAATSA प्रतर्बिंधों को माफ करने का अधिकार दिया गया।

## रूस की S-400 ट्रायम्फ मसिाइल प्रणाली:

■ **परचिय:**

- यह रूस द्वारा **डज़ाइन कया गया एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मसिाइल** प्रणाली (SAM) है।
- यह दुनिया में सबसे खतरनाक परचालन हेतु तैनात 'मॉडर्न लॉन्ग-रेंज एसएसएम' (MLR SAM) है, जसि अमेरिका द्वारा वकिसति **टरमनिल हाई एल्टीटयुड एरिया डफिंस' ससि्टम (THAAD)** से काफी उन्नत माना जाता है।
- यह एक मल्टीफंक्शन रडार, ऑटोनॉमस डटिक्शन एंड टारगेटिंग ससि्टम, एंटी-एयरक्राफ्ट मसिाइल ससि्टम, लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एकीकृत करता है।
- यह सतही रक्षा के लिये तीन तरह की मसिाइल दागने में सक्षम है।
- यह प्रणाली 30 कर्मिी तक की ऊँचाई पर 400 कर्मिी की सीमा के भीतर वमिन, मानव रहति हवाई वाहन (यूएवी) और **बैलसि्टिक तथा करुज मसिाइलें** सहति सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को नशाना बना सकती है।
- यह प्रणाली 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से छह पर एक साथ नशाना लगा सकती है।

■ **भारत के लिये महत्त्व:**

- भारत के दृष्टिकोण से चीन भी रूस से रक्षा उपकरण खरीद रहा है। वर्ष 2015 में चीन ने रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कयि। और इसे जनवरी 2018 में शुरू कया गया था।
- चीन द्वारा S-400 प्रणाली के अधगिरहण को इस क्षेत्त्र में **"गेम चेंजर"** के रूप में देखा गया है। हालाँकि भारत के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता सीमति है।
- इसका अधगिरहण दो मोर्चों पर युद्ध में हमलों का मुकाबला करने के लिये महत्त्वपूर्ण है, यहाँ तक कि इसमें उच्च स्तरीय **फ-35 यूएस लडाकू वमिन** भी शामिल है।

## भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर CAATSA छूट:

- NDAA संशोधन ने अमेरिका से रूस नरिमति हथियारों पर अपनी नरिभरता से भारत की धुरी को दूर करने में सहायता के लिये और कदम उठाने का भी आग्रह कया।
- यह संशोधन हाल के **द्वपिक्षीय सामरिक संबंधों की अवधि के अनुरूप है।**
  - महत्त्वपूर्ण वर्ष 2008 था और तब से भारत के साथ अमेरिकी रक्षा अनुबंध कम-से-कम 20 बलियन अमेरिकी डॉलर तक का है। वर्ष 2008 से पहले की अवधि में यह केवल 500 मलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - इसके अलावा वर्ष 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी। **कवाड** और अब **I2U2** जैसे समूहों के माध्यम से रणनीतिक संबंधों को भी मज़बूत कया गया है।
- **भारत के लिये रूसी मंचों से दूर जाना उसके सामरिक हति में है।**
  - यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद चीन पर रूस की नरिभरता काफी बढ़ गई है, एक ऐसी स्थिति जसिमें भविष्य में बदलाव की संभावना नहीं है।
  - पहले से ही रूस के हथियारों के नरियात के दूसरे सबसे बड़े प्राप्तकर्त्ता के रूप में चीन भारत के बाद दूसरे स्थान पर है।
  - चीन के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे सीमा प्रबंधन प्रोटोकॉल को देखते हुए रूसी हथियारों पर नरिभरता नासमझी है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस